भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

COMMUNIST PARTY OF INDIA (MAOIST)

मैनपुर डिवीजनल कमेटी

Mainpur Divisnol Committee

प्रेस स्टेटमेंट **दिनांक : 23 मार्च 2014**

मैनपुर डिवीजन की जनता से माओवादियों का आव्हान

सीतानदी-उदंती अभ्यारण्य के नाम से जनता को उजाड़ने की साजिश के खिलाफ, वन अभ्यारण्य में तेंदुपत्ता सहित तमाम वनोपजों पर जनता के अधिकार के लिए, सिंचाई खातिर बिजली-पानी की उचित व्यवस्था के लिए

लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करो! जन आंदोलन की राह चुनो!

प्यारी जनता

आपके खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाने वाले लोकसभा चुनाव फिर पांच साल के बाद आ गए हैं. केंद्र में पीछले दस सालों से कांग्रेस की सरकार रही और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार. दोनों ने मिलकर हमारे छत्तीसगढ़ को बेच खाया है. आज फिर भाजपा के चंदूलाल साहू और कांग्रेस के अजीत जोगी जनता को धोखा देने के लिए झूठे वायदे और आश्वासन दे रहे हैं. हमारी जनता से अपील है कि इन बरसाती मेंढकों के धोखे में न आएं, ये केवल पांच साल में एक बार आकर वोट लूट कर ले जाने वाले हैं. अगर आपको अपनी बुनियादी और मौलिक समस्याओं का हल करना है तो केवल और केवल जन आंदोलन की एकमात्र रास्ता है.

सीतानदी-उदंती को अभ्यारण्य घोषित कर इसे आमामोरा तक बढ़ाया जा रहा है. कुछ बाघों के लिए हजारों आदिवासी-गैर आदिवासी भाइयों को उजाड़ा जा रहा है. कुछ बाघों के लिए सरकार सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर रही है जबकि इलाके की जनता को दाने-दाने के लिए तरसा दिया गया है. अभ्यारण्य के गांवों को विकास से सैकड़ों कोसों दूर रखा जा रहा है. बहाना बनाया जा रहा है माओवादियों के डर को! वन अभ्यारण्य से जनता को तेंदुपत्ता नहीं तोड़ने दिया जाता, आवंला, शहाद, गोंद, जड़ी-बुटियों का संग्रहण व बेचना भी गैर कानून घोषित कर जंगल में रहने वाले सभी नागरिकों को अपराधी बना दिया गया है. यह सब जनता को विस्थापित कर यहां पर विदेशी व दलाल पूंजीपतियों की कंपनियों को लूटेने के लिए जगह देने के लिए किया जा रहा है. पूरे राज्य में तेंदुपत्ता की रायल्टी ठेकेदारों से प्रति मानक बोरा २००० से लेकर ४००० तक सरकार वसूल करती है. लेकिन जनता को मात्र १२०० रुपये प्रति मानक बोरा दिया जाता है.

वन अभ्यारण्यों के गांवों हो या राजस्व ग्राम सभी को उजाड़ने की तैयारी है. केंद्र की कांग्रेस व राज्य की भाजपा सरकार ने मिलकर पूरे अभ्यारण्य को कोर एरिया घोषित कर दिया है. अब आसपास के राजस्व ग्रामों को बफर एरिया बनाया जा रहा है इससे विस्थापन की तलवार सभी गांवों पर लटक गयी है. इसलिए गरियाबंद के देवभोग, अमलीपदर, उदंती, सीतानदी सभी जगह पट्टों के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है. असली पट्टे देने की बजाय वन विभाग द्वारा 'अधिकार पत्रक' दिये जा रहे हैं. यह न तो जमानत के काम आते न ही बैंकों में चलते. यह जनता के साथ सरासर धोखा है.

किसानों को सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं है. सुंडरु, सिकासेर, दुधवा और गंगरेल जैसे बांध बनाये लेकिन सारा पानी जाता है पूंजीपतियों के कारखानों के लिए शहरों में! ५० साल हो चुके हैं आज तक कोई मुआवजा वहां की जनता को नहीं दिया गया. किसानों को सिंचाई के लिए दी जाने वाली बिजली में हर रोज कटौती की जाती है, जिससे फसलें तबाह हो रही हैं, किसान कर्जदार हो रहे हैं. उनको आत्महत्या की तरफ सरकार द्वारा धकेला जा रहा है. वन ग्रामों सहित जंगल के अन्य गांवों में भी बिजली की लाइन नहीं बिच्छाई जा रही, जबकि जनता अधिकारियों के चक्कर लगा-लगा कर थक चुकी है. इससे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

मैनपुर डिवीजन को पुलिस, सीआरपीएफ के कैंपों व थाने लगाकर सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया है. दर्जनों नए भवन बनाए जा रहे हैं. हजारों फोर्स को तैनात किया जा रहा है लेकिन रिसगांव व उदंती जैसे गांवों में जहां हस्पताल के भवन भी बन गए हैं, दो एमबीबीएस डॉक्टर सरकार को तैनात करने के लिए नहीं मिल रहे.

प्रिय जनता!

इलाके में दिनों दिन दमन केवल माओवादी पार्टी को खत्म करने के लिए नहीं चलाया जा रहा. इस पूरे इलाके को इस लिए सैनिक छावनी में तब्दील किया जा रहा है ताकि यहां से जनता को विस्थापित किया जा सके और जनता के आंदोलन को दबाया जा सके और कोई अभ्यारण्य के खिलाफ आवाज न उठाये. इसलिए आपसे अपिल है कि कोई भी पार्टी जनता की भलाई के लिए चुनावों में नहीं उतरती. आइये अपने अधिकारों के लिए खुद संघर्ष करें. और उपरोक्त मांगों को लेकर लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करें!

चुनावों से केवल सरकार बदलती है - व्यवस्था नहीं! सच्चे लोकतंत्र के लिए,

बुनियादी समस्याओं के हल के लिए माओवादी जनयुध्द एकमात्र रास्ता है!

प्रवक्ता

मैनपुर डिवीजनल कमेटी

ओड़िशा राज्य कमेटी